जैव विविधता के लिए बचाने होंगे वन

के. जयलक्ष्मी

महात्मा गांधी ने कहा था कि हम दुनिया के वनों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, वह इस बात का प्रतिबिंब है कि हम स्वयं और दूसरे इन्सानों के साथ क्या कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया है। इसका मकसद कार्बन को अपने में समाहित करने वाले अद्भुत जंगलों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन हमारे जंगलों की आज जो दशा है, वह क्या किसी से छिपी है?

करीब 40 देशों में काम करने वाली संस्था 'कंज़र्वेशन इंटरनेशनल' ने 10 ऐसे वनों की सूची जारी की है जिन पर सर्वाधिक खतरा मंडरा रहा है। इन जंगलों में 90 फीसदी या उससे भी ज़्यादा प्राकृत वास खत्म हो चुके हैं। यदि ये वन पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली वनस्पतियों की करीब 1500 दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। ये वन भारत से लेकर वियतनाम और न्यूज़ीलैंड, भारत-मलेशिया द्वीप समूह, फिलीपींस, दक्षिण-पश्चिम चीन, पूर्वी ब्राज़ील, उरुग्वे, कैलिफोर्निया, तटीय पूर्वी अफ्रीका, मेडागास्कर और हिंद महासागर के अन्य द्वीपों, इथियोपिया, तंज़ानिया तथा मलावी के क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इनमें अधिकांश वन अर्धकटिबंधीय या कटिबंधीय नम वन हैं। ये मानव विकास के कारण अत्यंत दबाव में हैं।

वन तेज़ी से फैलते शहरों, चारागाहों, कृषि और खदानों की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा करके हम स्वयं अपने जीवन को ही खतरे में डाल रहे हैं। इस चिंता को हम हाशिए पर डाले हुए हैं, लेकिन सच कहें तो यह खतरनाक हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2010 के बीच हर साल जंगलों के क्षेत्रफल में 52 हज़ार वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। हालांकि इसके पहले के दशक से तुलना करें तो स्थिति में आंशिक सुधार नज़र आता है। इस दशक के दौरान वनों के नष्ट होने की गति 83 हज़ार वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष रही थी। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि नष्ट होने वाले जंगलों में कितने पुराने थे और कितने नए।

वन वृक्षों का समूह-भर नहीं होता। ये जैव विविधिता से संपन्न ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जीवन की विविधता को बनाए रखते हैं। यही वजह है कि अनेक लोग जंगल विनाश व बरबादी जनित उत्सर्जन में कमी (आरईडीडी) जैसी योजनाओं के प्रति आशंकित हैं। यह वन की अवैज्ञानिक परिभाषा पर आधारित है जिसमें एक ही प्रजाति के पौधों और यहां तक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले पौधे रोपे जाते हैं। इससे भी बढ़कर, आरईडीडी जंगलों के विनाश के अंदरूनी कारकों का समाधान नहीं करती। यही वजह है कि संरक्षित क्षेत्रों में तो वनों की कटाई कम हो सकती है, लेकिन गैर संरक्षित क्षेत्रों में नहीं। इससे भी बदतर बात यह भी है कि आरईडीडी उत्तरी देशों में औद्योगिक इकाइयों की अनुमति देती है जो प्रदूषण फैलाती हैं और इस तरह वातावरण लगातार खराब होता जा रहा है।

चित्र : बोस्की जैन

ब्रिटिश सरकार अपने 15 वन क्षेत्रों को बेचने का वादा कर चुकी है। यह कुल मिलाकर 40 हज़ार हैक्टर के बराबर क्षेत्रफल होगा। यह इस उम्मीद में किया जा रहा है कि इससे उसके खज़ाने में 10 करोड़ पाउंड की बढ़ोतरी हो सकेगी।

उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि एशिया में जितने जंगल कट रहे हैं, मलेशिया में उससे तिगुनी रफ्तार से वन खत्म हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश जंगल जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत सम्पन्न बोर्नियो द्वीप में समाप्त हो रहे हैं। नीदरलैंड्स स्थित पर्यावरण समूह वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा किए गए इस विश्लेषण के अनुसार बोर्नियो में स्थित मलेशियाई प्रांत सारावाक में पिछले पांच साल के दौरान ही 10 फीसदी जंगल समाप्त हो गए, जबकि बाकी एशिया में इस अवधि में वनों के कटाई की दर 3.5 फीसदी रही। सारावाक के पीटलैंड में कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो खतरे में हैं। इनमें सुमात्रा का गैंडा, बोर्नियो का तेंदुआ और पिग्मी हाथी शामिल हैं।

वन कितने कीमती हैं, इसके सही मूल्यांकन का सख्त अभाव यहां साफ नज़र आता है। अगर हम सही मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि इससे न केवल जंगल में रहने वाले गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि नया बाज़ार भी खुलेगा और वैश्विक आर्थिक विकास भी होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की एक रिपोर्ट पर विश्वास करें तो सरकारों और दानदाता एजेंसियों ने वनों के आर्थिक लाभों को कम करके आंका है।

वनों को पारंपरिक रूप से उनके मुख्य वाणिज्यिक स्रोत इमारती लकड़ी के लिए महत्त्व दिया जाता है। लेकिन धरती पर पाई जाने वाली जैव विविधता का 80 फीसदी हिस्सा वनों की देन है। साथ ही ये कई तरह की इकोसिस्टम सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे स्वच्छ पानी ये देते हैं, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। धन के रूप में इसका आकलन करें तो यह योगदान 720 अरब डॉलर सालाना के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के गरीब लोगों को उनकी प्रत्यक्ष आजीविका जैसे भोज्य पदार्थों, औषधियों, ईंधन, ऊर्जा, रोज़गार इत्यादि उपलब्ध कराने में भी वनों का अहम योगदान है। यह 130 अरब डॉलर सालाना के तुल्य बैठता है।

आईयूसीएन की रिपोर्ट के लेखकों में से एक ल्यूसी एमर्टन कहती हैं, 'सरकारें बजट तय करते समय आम तौर पर स्थानीय लोगों द्वारा नियंत्रित वनों में निवेश के आर्थिक रिटर्न की गणना नहीं करती हैं। इस तरह से वे गरीबी को कम करने, आर्थिक विकास दर को बढ़ाने और टिकाऊ विकास का महत्त्वपूर्ण अवसर खो देती हैं।'

दुनिया में 40 करोड़ हैक्टर जंगल यानी युरोपीय संघ के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र और करीब डेढ अरब लोग यानी चीन की आबादी से ज़्यादा लोग स्थानीय नियंत्रित वानिकी में संलग्न हैं। हालांकि जंगलों पर उन्हें केवल 47 फीसदी वैधानिक अधिकार ही दिए गए हैं।

आईयूसीएन की 'स्थानीय नियंत्रित वानिकी में निवेश का मूल्य' शीर्षक से जारी हुई इस रिपोर्ट का मकसद यह दिखाना है कि अगर वनों का प्रबंधन उनमें या उनके आसपास रहने वाले लोगों द्वारा किया जाए तो उसका अर्थ व्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा। यह व्यवस्था जंगलों के निजीकरण करने के ब्रिटिश प्रयासों के बिलकुल विपरीत है।

आईयूसीएन के पर्यावरण एवं विकास निदेशक स्टीवर्ट मैगिनिस कहते हैं, 'स्थानीय लोगों द्वारा नियंत्रित वन प्रबंधन लाभदायक सार्वजनिक निवेश है और विकास में सहायक है। हम वैश्विक अर्थ व्यवस्था में बदलाव के संपूर्ण क्रांतिकारी तरीके और बेहतरी के लिए परिवर्तन की बात कर रहे हैं।'

वन इमारती लकड़ी, भोजन, आसरा और मनोरंजन के स्रोत के रूप में अनेक देशों के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पानी मुहैया करवाने, मिट्टी के कटाव को रोकने और कार्बन को सोखने के स्रोत के रूप में वनों की जो क्षमता है, उसका भी पूरी तरह से दोहन करने की ज़रूरत है।

वनों के कुछ लाभ इस तरह हैं :

• **वे हर तरह से जीवन के लिए ज़रूरी हैं :** जो सांस हम लेते हैं, वह वनों से मिलती है, भोजन और पानी हमें वनों से मिलता है, जीवन बचाने वाली औषधियां हमें वनों से

मिलती हैं, जीवन की विविधता हमें वन प्रदान करते हैं, हमारे वर्तमान व भविष्य को आकार प्रदान करने वाले वातावरण का निर्माण वन करते हैं। हमारी हर चीज़ तो वनों पर निर्भर है।

• वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के हमारे प्रयासो में वन महत्त्वपूर्ण सहयोगी हैं : वैश्विक प्रदूषण को कम करने का वनों से प्रभावी, सस्ता और तेज़ अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। इसका वैश्विक अर्थ व्यवस्था पर कितना दूरगामी असर पड़ सकता है, इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि अगर 2010 से 2012 के बीच इस प्रदूषण को आधा कर दिया जाए तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर की बचत होगी।

• आर्थिक विकास में वन अतुलनीय योगदान देते हैं : वनों पर निर्भर समुदायों की एक चौथाई आय जंगलों द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले पदार्थों और सेवाओं से मिलती है। आईयूसीएन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों द्वारा नियंत्रित वन गरीबों को हर साल 130 अरब डॉलर के बराबर लाभ पहुंचाते हैं।

• उजड़े जंगलों को बसाना : उजड़े और नष्ट हो चुके जंगलों को फिर से बसाने में भी बहुत सारे अवसर सामने आ सकते हैं। इससे अनेक लोगों को आजीविका मिल सकती है।

2010 को हमने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष के रूप में मनाया था। इस दौरान 90 देशों के 1500 सरकारी संगठनों, 388 गैर सरकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र की 21 एजेंसियों ने जैव विविधिता के महत्त्व को लेकर जागरूकता फैलाने में योगदान दिया। संयुक्त राष्ट्र ने 2011-2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक घोषित किया है। जैव विविधिता के सम्बंध में अक्टूबर में नागोया में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि वह संधि थी, जिसमें दुनिया के 191 देशों ने तय किया था कि वे धरती की 17 फीसदी ज़मीन और महासागरों के 10 फीसदी हिस्से को जैव विविधता के संरक्षण के लिए अलग रखेंगे। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह स्वीकारोक्ति थी कि जैव विविधता के नष्ट होने की भारी कीमत मानवता को आर्थिक एवं स्वास्थ्य के मोर्चे पर चुकानी होगी। यह नुकसान 3 से 4 अरब डॉलर सालाना से कम नहीं होगा। इसी भारी नुकसान के कारण विश्व बैंक और विभिन्न देशों के वित्त मंत्रियों के कान खड़े हुए हैं। यह वह नुकसान है, जिसे कोई भी सरकार वहन नहीं कर सकती।

पर्यावरणीय स्वास्थ्य के आर्थिक मूल्यांकन पर तीन साल के अध्ययन का नतीजा था रिपोर्ट 'द इकॉनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी' (टीईईबी) जिसे इस बैठक में जारी किया गया। इसमें आह्वान किया गया है कि खत्म हो रही जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दे को भी जलवायु परिवर्तन के समान ही महत्त्व दिया जाना चाहिए। अगर भारत को ही लें तो यह दुनिया के 17 सर्वाधिक विविधता वाले देशों में शामिल है। यहां 10 अलग-अलग बायोग्राफिक ज़ोन हैं, जिनमें रेगिस्तान से लेकर वेटलैंड्स, मालाबार के तटों से लेकर हिमालय के पर्वत तक शामिल हैं। जहां तक जंगलों का सवाल है, यहां 16 बड़े और 251 अन्य प्रकार के वन हैं।

इस बीच, एक हालिया रिपोर्ट कहती है कि अमेज़न के जंगलों में आए एक भयंकर सूखे के कारण अनगिनत पेड़ नष्ट हो गए। इससे वर्षावनों का यह विशाल क्षेत्र कार्बन सोखने की बजाय कार्बन उत्सर्जन करने वाले इलाके में तब्दील हो गया है। पत्रिका 'साइंस' की एक रिपोर्ट में लीड्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक कहते हैं कि अमेज़न के जंगलों में वृक्षों के खत्म होने की वजह से अकेले अमरीका में ही जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में पिछले साल 5.4 अरब टन की बढ़ोतरी की आशंका है। अमेज़न में 2005 के दौरान जो भयावह सूखा पड़ा था, उसकी वजह से 18,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बारिश में कमी हो गई थी। इससे वातावरण में 5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची थी।

अमेज़न के जंगल आम तौर पर हर साल 1.5 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, लेकिन लीड्स के अनुसंधानकर्ताओं ने आगाह किया है कि ग्लोबल वार्मिंग से यह भूमिका पलट भी सकती है। यानी अमेज़न के जंगल कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की बजाय उसे उत्सर्जित करने लग सकते हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***